संपादकीय

जनसत्ता 4 अगस्त, 2014 : पछिले हफ्ते भारत के रुख के कारण वशि्व व्यापार संगठन का प्रस्तावति ट्रेड फैसलिटिशन □ग्रीमेंट यानी सुगम व्यापार समझौता अधर में लटक गया□ डब्ल्यूटीओ के उन्नीस साल के इतहिास में मतभेदों और ववािद का सलिसलिा चलता रहा है□ पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नयिम-कायदों को □क वैश्वकि समझौते की शक्ल मलिने की उम्मीद की जा रही थी□ टी□फ□ के लि□ इक्तीस जुलाई की समय-सीमा तय की गई थी□ लेकनि भारत की ओर इस समझौते की पुष्ट िन होने से टी□फ□ के भवषि्य पर सवालयिा नशिान लग गया है□ अमेरकिा, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलयिा और जापान जहां भारत के रुख को बेजा जदि मानते हैं, वहीं मोदी सरकार ने साफ कयिा है क िउसके फैसले के पीछे अपने कसिानों के हतिों और खाद्य सुरक्षा की फक्रि है□ यह ववािद नया नहीं है, दोहा दौर की वार्ता□ं शुरू होने के वक्त से ही चला आ रहा है□ पछिले साल दसिंबर में बाली में हु□ डब्ल्यूटीओ के नौवें मंत्रस्तिरीय सम्मेलन में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा था□ तब □क समय लग रहा था क िरस्साकशी के चलते सम्मेलन नाकाम हो जा□गा और दोहा दौर की वार्ताओं को पटरी पर लाने की सारी कवायद बेकार चली जा□गी□ ऐसे में □क बीच का रास्ता नकिला गया□ प्रस्तावति समझौते में 'शांत िअनुच्छेद' जो□ा गया, जसिके मुताबकि कृष ि सबसडिी या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की सरकारी खरीद सीमति करने का प्रावधान चार साल तक लागू नहीं होगा, यानी तब तक इस छूट के खलिाफ डब्ल्यूटीओ के ववािद नपिटारा प्राधकिरण में अपील नहीं की जा सकेगी□

वकिसति देश बाली में हुई इसी सहमत िका हवाला देकर भारत सरकार के नरि्णय की आलोचना कर रहे हैं□ लेकनि भारत का कहना है क िवह टी□फ□ के खलिाफ नहीं है, वह चाहता है क िइसे मंजूर करने के साथ-साथ खाद्य सबसडिी के मसले का अंतरमि नहीं बल्क िस्थायी हल नकिला जा□□ वकिसति देश चाहते हैं क िन्यूनतम समर्थन मूल्य कुल उपज के दस फीसद तक सीमति रहे□ पर समस्या सरि्फ यही नहीं है□ न्यूनतम समर्थन मूल्य के लि□ वर्ष 1980 को आधार बनाया गया है□ अगर ये सब बातें मान ली जा□ं तो भारत के कसिानों के लि□ जो थो□ी-बहुत राहत की व्यवस्था चली आ रही है उस पर ग्रहण लग जा□गा□ वकिसति देशों की चतिा सरि्फ यह है क िकसि तरह आयात-नरि्यात के नयिम और उदार हों और उन्हें दुनयिा भर के बाजारों में अपनी पहुंच ब□ाने में कोई अ□चन न रहे□ लेकनि इस मामले में खुद उनका व्यवहार वरिोधाभासों से भरा रहा है□ वे जब-तब शुल्कीय और गैर-शुल्कीय बाधा□ं ख□ी करने से बाज नहीं आ□□ अब वे वशि्व व्यापार संगठन का भवषि्य खतरे में प□ जाने या कम से कम टी□फ□ का सपना साकार न हो पाने का दुख जताते हु□ सारा दोष भारत पर म□ रहे हैं□

लेकनि दुनयिा के वभिन्नि देशों की परस्थितियिां □क जैसी नहीं हैं, और वशि्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में रह-रह कर उभरते रहे गतरिोध की यही वजह रही है□ उन्हें भारत की वशिेष स्थतियिों को ध्यान में रख कर उसके रुख पर सहानुभूतपूिर्वक सोचना चाह□□ अगर टी□फ□ को वे दबाव डाल कर मनवा लेते हैं और कृष ि सबसडिी का मसला अनसुलझा रह जाता है तो क्या भवषि्य में समस्या ख□ी नहीं होगी? अगर चार साल बाद कसिी देश के खलिाफ न्यूनतम समर्थन मूल्य की सीमा लांघने की शकियत आ□गी तो संभावति कार्रवाई से न□ ववािद उठेंगे और टी□फ□ दोराहे पर होगा□ इसलि□ इक्तीस जुलाई की जो समय-सीमा तय की गई थी, उसे अंतमि न मान कर जनिेवा में होने वाली अगली बैठक में फरि से सर्वसम्मत िकी कोशशि की जा सकती है□ क्या कृष ि सबसडिी के मसले को डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता?

फेसबुक पेज को लाइक करने के लि□ क्लकि करें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्वटिर पेज पर फॉलो करने केलि क्लकि करें- https://twitter.com/Jansatta